मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

सभी देवी देवताओं को सूचित किया जाता हैं कि वो अपनी अपनी जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए भाजपा कार्यालय में जायें- योगी आदित्यनाथ

अभिभावकों को निशाना बनाया 3
स्मार्ट सिटी एक ख्वाब 4
देश के एटीएम बंद क्यों 5
बात राम के घर की नहीं 6
किसान तुम्हारे मुखौटे उतारेंगे 8

वर्ष 33 अंक -3 फ़रीदाबाद 02-08 दिसम्बर 2018 फोन : - 9999595632 ₹2.50

हरामखोरों की रिश्वतखोरी के चलते ऑडिटोरियम तो कंडम होना ही था

निर्माण कराने वाले अफ़सरों की कोठियां कभी कंडम नहीं होंगी

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब 80 लाख की लागत से बना स्मार्ट सिटी का एक मात्र म्यूनिसिपल ऑडिटोरियम कंडम हो चुका है। लेकिन इसे कंडम घोषित करने से पहले मरम्मत के नाम पर भी लाखों हड़पे जायेंगे तथा कंडम घोषित करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिये आईआईटी दिल्ली व रुड़की से विशेषज्ञ भी बुलाये जायेंगे, जाहिर है उस पर भी लाखों खर्च होंगे। यानी इसके निर्माण के समय तो तत्कालीन अफ़सरों ने मोटा माल मारा ही था, अब कंडम होने पर भी आज के अफ़सरों को कुछ न कुछ तो देकर ही जायेगा।

35 वर्ष पूर्व इस ऑडिटोरियम का शिलान्यास करके तालियां बजवाई थी तत्कालीन विधायक एवं स्थानीय स्वशासन मंत्री एसी चौधरी ने, लेकिन इसके निर्माण के नाम पर जो घोटाले हुये उनके प्रति चौधरी ने आंखें बंद रखीं अथवा वे भी लूट में से अपना हिस्सा लेते रहे होंगे। करीब 10 साल तक इसका निर्माण कार्य चला। 10 माह में पूरा होने वाला काम जब 10 वर्ष में पूरा होता है तो समझ लो घोटाला हो गया। इस बीच कई ठेकेदार आये और गये, कई अफ़सर भी आये और गये। हर नया आनेवाला ठेकेदार व अफ़सर अपना हिस्सा पहले डकारता है। इसी चक्कर में बजट बढता जाता है। निर्माण सामग्री महंगी और क्वालिटी हल्की होती जाती है।

10 साल में निर्माण कार्य पूरा होने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल ने इसका लोकार्पण करके तालियां बजवाई। लेकिन यह कहने की हिम्मत किसी में न हुई कि शहर की जनता के सिर पर जनता का ही जूता मारा जा रहा है। चारों ओर केवल चापलूसों का घेरा तालियां पीट रहा था। दस साल तक चले इस घोटाले के बारे में पता तो बहुतों को था परन्तु मुंह खोलने की हिम्मत किसी में न थी।

रिश्वत का गवाह : रिश्वत से बना, रिश्वत से गिरेगा भी!

निगमायुक्त शाइन हरामखोरी व रिश्वतखोरी का विकल्प मानते हैं सलाहकार को

फ़रीदाबाद (म.मो.) नगर निगम के तमाम पार्षद कुछ समय से आरके गर्ग नामक एक सलाकार को हटाने का संघर्ष छेड़े हुए हैं। निगम द्वारा नियुक्त एक अन्य सलाहकार कटारा के इतिहास भूगोल से तो सारा शहर खूब वाकिफ़ है क्योंकि उन्होंने एसडीओ से लेकर चीफ़ इन्जीनियर तक के पद पर रहते हुये जी भर कर लूटा था इस शहर को लेकिन गर्ग के इतिहास बारे में अभी तक कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। इस सलाहकार से परेशान पार्षद, जो कभी एकजुट नहीं होते थे, एक हो गये और कमिश्नर को उसे हटाने के लिये मजबूर कर दिया। लेकिन कमिश्नर ने उन्हें हटाने का प्रयास स्वीकार करते हुये उनकी उपयोगिता का बखान कुछ इस तरह किया कि उनके रहने से निगम को काफ़ी लाभ हो रहा था।

इस बाबत उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बल्लबगढ़ के सेक्टर 3 में एक मोबाइल कम्पनी ने अपनी केबल अथवा पाइप लाइन डालनी थी। इसके एवज में सम्बन्धित एसडीओ ने हिसाब-किताब लगाकर मात्र सात लाख रुपये की देनदारी निकाली। यानी कम्पनी नगर निगम को इस काम के बदले केवल सात लाख रुपये अदा करेगी। जब यही फ़ाइल उन्होंने सलाहकार गर्ग को भेजी तो उन्होंने सही हिसाब लगाकर 54 लाख की देनदारी निकाली। यानी एसडीओ ने नगर निगम को इस छोटे से काम में 47 लाख रुपये की चपत लगा दी थी जिसे सलाहकार ने बचा लिया।

सवाल यह पैदा होता है कि एसडीओ के ऊपर बैठे एक्सीयन-I, एससी व चीफ़ इन्जीनियर क्या नगर निगम के बराती हैं? क्या उन्हें फ़ाइल पढ़ने नहीं आती थी? क्या इस तरह की फ़ाइल केवल सलाहकार ही पढ़ सकता है? अगर ऐसा है तो जनता के सिर पर इन नाकारा इन्जीनियरों का बोझ क्यों लाद रखा है? इन सब की छुट्टी करके क्यों न सारा काम सलाहकार महोदय को सौंप दिया जाय?

दरअसल मसला केवल एक एसडीओ या सेक्टर 3 का नहीं है, मसला पूरे नगर निगम व इसके तमाम इन्जीनियरों एवं अधिकारियों का है जिसकी जितनी औकात होती है वह उतना ही माल डकार जाता है। उक्त उदाहरण में एसडीओं ने जो 47 लाख की चपत नगर निगम को लगा दी थी उसमें नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारी शामिल थे। इस तरह के हरामखोर एवं रिश्वतखोर अधिकारियों से निबटने के लिये सलाहकार रखना कोई उचित उपाय नहीं है। उचित उपाय तो केवल यही होता कि इस घोटाले का विधिवत संज्ञान लेकर सभी सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ़ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराके उन्हें नौकरी से फ़ारिग कर दिया जाता। सवाल एक यह भी है कि इन्जीनियरों तथा अन्य कर्मियों की नियुक्ति होती कैसे है? क्यों नहीं नगर निगम के लिये सही तरीके से सही ढंग के अधिकारियों का चयन किया जाता?

घोटाले का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 50 साल पुराना बल्लबगढ का आकाश सिनेमा व 55 साल पुराना नीलम सिनेमा आज भी सही सलामत खड़ा है, 38 वर्ष पूर्व बना सेक्टर 7 का सत्यपैलेस सिनेमा हॉल अगले 50 साल भी हिलने वाला नहीं। इस ऑडिटोरियम के निर्माण के समय तैनात एसई रनोलिया व एक्सईएन कटारा की उसी वक्त की बनी कोठियां तो ज्यों की त्यों हैं, फ़िर जनता का यह ऑडिटोरियम कैसे कंडम हो गया? नया ऑडिटोरियम बनाने के नाम पर लूट का नया सिलसिला शुरू करने की अपेक्षा पुराने घोटाले की जांच ज़्यादा जरूरी है। जांच तो किसने क्या करानी है उसी कटारा को सेवानिवृत हो जाने के बाद फ़िर से सलाहकार नियुक्त करके शहर को स्मार्ट बनाने का दायित्व सौंपा गया है। समझा जा सकता है कि जितना स्मार्ट उन्होंने ऑडिटोरियम बनवाया था, उससे कम स्मार्ट तो वे क्या ही बनायेंगे इस शहर को।

आये दिन जनसभाओं में नेतागण तालियां बजबाने के लिये घोषणा करते हैं कि अमुक काम पर कितने सौ करोड़ खर्च किये जायेंगे। अथवा फलां परियोजना पर कितने करोड़ खर्च कर दिये गये हैं। लेकिन यह जानने व बताने का प्रयास कोई नहीं करता कि इतनी भारी भरकम रकमों में से कितना पैसा ये नेतागण व इनके लगुये-भगुये डकार गये हैं अथवा डकारने की तैयारी में हैं। यदि नेताओं द्वारा घोषित पूरी रकम ईमानदारी से खर्च की जाय तो न तो ये म्युनिसिपल ऑडिटोरियम कंडम होता और न ही तमाम सरकारी बिल्डिंगें, सड़कें सीवर लाइने आदि समय से पहले कंडम न होते।

इस तरह से असमय जन-उपयोगी सेवाओं का कंडम हो जाना खुले भ्रष्टाचार को दर्शाता है और आज की खट्टर सरकार द्वारा इसका संज्ञान न लेना उनकी मिली भगत को सिद्ध करता है। (पेज तीन भी देखें)

नीरा राडिया कांड के दाग़ी सुनील अरोड़ा को बनाया मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

तीन राज्यों के चुनाव की गहमा गहमी के बीच ' न खाऊँगा न खाने दूँगा' वाले मोदीजी ने चुपके से सुनील अरोड़ा की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कर दी है और वही 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। 2019 की तैयारी में मोदीजी कोई कोर-कसर छोड़ नही रहे हैं। तभी उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर ऐसे दागी व्यक्ति की नियुक्ति की है जो नीरा राडिया वाले केस में शामिल रहे हैं।

राजस्थान कैडर के आइएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा एयर इंडिया के सीएमडी रह चुके हैं। राडिया टेप कांड में सुनील अरोड़ा के साथ हुई बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट के सामने आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एविएशन के क्षेत्र में लॉबिंग एक्टिविटी की जाँच करने को कहा था।

वैसे नीरा राडिया का नाम सुनते ही आज के नामचीन बड़े पत्रकारों की कलम की स्याही भी सूख जाया करती है।इसलिए इस मुद्दे पर कोई कुछ लिखने की जहमत नही उठा रहा है। लगता नही है कि रवीश कुमार इस मुद्दे को लेकर प्राइम टाइम करेंगे और न ही पुण्यप्रसुन वाजपेयी किसी टीवी शो में दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपने 2010 मे लिखे हुए ब्लॉग को याद करेंगे जिसमे वह लिखते हैं.....नीरा राडिया के फोन टैप से इंडियन एयरलाइंस के पूर्व सीएमडी सुनील अरोड़ा के जरिये सीबीआई बीजेपी को भी घेरने की तैयारी में है। क्योंकि एयरलाइंस को लेकर जो भी गफलत सुनील अरोड़ा ने

की वह तो राडिया फोन टैपिंग में सामने आया ही है कि आखिर कैसे सुनील अरोड़ा नीरा राडिया की पहुंच का इस्तेमाल कर एंडियन एयरलाइन्स के मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहते थे। लेकिन सीबीआई की नजर सुनील अरोड़ा के जरिये राजस्थान में करोड़ों की जमीन को कुछ खास लोगों को दिलाने में किसकी भूमिका थी, इस पर है। क्योंकि सुनील अरोड़ा राजस्थान में तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे। और तब सत्ता बीजेपी के पास थी। और बतौर निजी सचिव बिना सीएम के हरी झंडी के जमीनों को कौडियों के मोल खरीद कर बांटने की कोई सोच भी नही सकता है। उसी दौर में राजस्थान की कई जमीने कुछ खास नौकरशाहों को नीरा राडिया के

शेष पेज दो पर